Central Sector of the Third Plan, enhancement of provision in the Fourth Plan was not found possible. One of the dredgers of the Minor Ports Dredging and Survey Organisation is now working at Bhavanagar and the other is at Caucutta during the guarantee period. The State Goveernment have already been informed that it might be possible to make one dredger available to them by the end of 1967.

(c) and (d). A proposal has just been received from the Government of Kerala for obtaining under the Colombo Plan the services of a foreign expert to conduct studies on minor ports in the State and to prepare a Master Plan for their development. This will be examined.

जम्मू तथा काश्मीर में चावल का मूल्य

3700. श्री राम गोपाल शालवाले :
श्री ओ० प्र० त्यागी :

क्या खाद्य तथा कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) काश्मीर में सरकारी दुकानों पर चावल किस भाव बेचा जाता है;

(ख) क्या यह सच है कि रिआयती दर पर चावल बेचने से होने वाला घाटा केन्द्रीय सरकार द्वारा पूरा किया जाता है;

(ग) काश्मीर में राज सहायता प्राप्त दरों पर खाद्यान्न बेचने पर पिछली तीन पंचवर्षीय योजनाओं में सरकार ने कुल कितनी राशि खर्च की;

(घ) क्या ये सुविधायें अन्य कुछ राज्यों को भी, जैसे बिहार के पहाड़ी क्षेत्र और उड़ीसा के आदिम जातीय क्षेत्र, दी गई हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इस के क्या कारण हैं ?

खाद्य, कृषि, सामुदायिक विकास तथा सहकार मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री अन्नासाहिब शिन्दे) : (क) 7 मार्च, 1967 को प्राप्त रिपोर्ट के आधार पर दरें 36 रुपये से 43 रुपये प्रति क्विंटल तक थीं ।

(ख) जी नहीं । केन्द्रीय निर्गम मूल्य में ही सम्मिलित राज सहायता जो सभी राज्यों को दी जाती है, को छोड़ कर भारत सरकार जम्मू तथा काश्मीर में उपभोक्ता मूल्य, जो भाग (क) में दिया गया है, को बनाये रखने के लिए कोई विशिष्ट राज सहायता नहीं देती है ।

(ग) से (ङ). प्रश्न ही नहीं उठते ।

Procurement and Selling Price of Wheat in U.P.

3701. Shri Baburao Patel: Will the Minister of Food and Agriculture be pleased to state:

(a) whether the Government of Madhya Pradesh raised the price of procurement and selling of local wheat;

(b) whether the State Government had obtained prior approval of the Centre to effect this rise;

(c) whether the Government have seen press reports that prices of wheat in local markets have suddenly shot up; and

(d) if so, the reaction of the Centre to the situation created by this action of the State Government?

The Minister of State in the Ministry of Food, Agriculture, Community Development and Cooperation (Shri Annasahib Shinde): (a) Yes, Sir.

(b) Procurement prices of wheat were got approved by the Central Government. Selling prices are not required to be approved by the Central Government.